INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 2, Issue: 01 | January - June 2022

कोरोना महामारी से प्रभावित भारतीय कर्मचारी एवं अनुसंधान संस्थान का आर्थिक प्रतिरूप

कैप्टन (डॉ.)सुनीता देवी
विभागाध्यक्ष – अर्थशास्त्र , देवता महाविद्यालय मोरना
बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत
drsunita1980@gmail.com

सार
कोविड–19 महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वायरस के प्रकोप के कारण देशव्यापी तालाबंदी हुई, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, मांग में झटका लगा और कृषि से लेकर सेवाओं तक के उद्योग प्रभावित हुए। यह शोध एक केस स्टडी के रूप में भारतीय चमड़ा उद्योग का उपयोग करते हुए, औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए महामारी के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करता है। यह भारतीय उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे आपूर्ति में व्यवधान, मांग में संकुचन, श्रम की कमी और लॉजिस्टिक अनिश्चितताओं पर प्रकाश डालता है। शोधइन चुनौतियों से पार पाने और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

मुख्य शब्दः
कोविड–19, भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, औद्योगिक क्षेत्र, आपूर्ति में व्यवधान, मांग में संकुचन, श्रम की कमी, आत्मनिर्भरता, वैश्विक विनिर्माण केंद्र।

परिचय

कोरोना वायरस (कोविड–19) चीन के वुहान से निकला और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में फैल गया। भारत ने 30 जनवरी, 2020 को केरल राज्य से अपना पहला सीओवीआईडी –19 मामला दर्ज किया और बाद में पूरे भारत में यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के कारण मार्च के महीने में यह महामारी भारत के कई राज्यों में फैल गई। जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने वायरस के संचरण को कम करने के लिए 25 मार्च, 2020 से पूरे देश में 55 दिनों का लॉकडाउन लागू किया। लेकिन चूंकि वायरस अत्यधिक परिवर्तनशील है, इसलिए वायरस का प्रसार बढ़ रहा है, लॉकडाउन का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सुधार करना और बड़े पैमाने पर फैलने की रोकथाम की तैयारी करना है, जो अब जुलाई के महीने में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसमें कोविड –19 है। देश में पॉजिटिव मामले 10 लाख के पार पहुंचे। आर्थिक शब्दावली में कहें तो, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने से बड़े पैमाने पर राजस्व हानि हुई क्योंकि सभी आर्थिक गतिविधियाँ लगातार 2 महीने से अधिक समय तक ठप रहीं। वर्तमान में राष्ट्र गतिविधियों के परिदृश्य को अनलॉक कर रहा है, जिसके तहत कुछ आर्थिक गतिविधियों को सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखने के एक निर्धारित प्रारूप के भीतर कार्य करने की अनुमति है।

यह एक संकट की स्थिति है जो प्रकृति में अभूतपूर्व है। इसलिए दुनिया भर में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कार्रवाइयों की बड़े पैमाने पर आलोचना हो रही है। विश्व नेता संयुक्त राज्य अमेरिका की वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक लॉकडाउन लेने में देरी के लिए आलोचना की गई, जिसके परिणामस्वरूप देश को बड़े पैमाने पर प्रकोप का सामना करना पड़ा जिसे बाद में नियंत्रित करना असंभव हो गया। अब, जहां तक भारत का सवाल है, विलंबित लॉकडाउन के लिए इसकी भी आलोचना की गई क्योंकि पहला सीओवीआईडी –19 मामला 30 जनवरी, 2020 को रिपोर्ट किया गया था और अभी भी फरवरी और मध्य मार्च के महीने में अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधित नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप देश को भारत के सभी प्रमुख राज्यों और शहरों में विविध प्रकोप का सामना करना पड़ा। जबकि, वियतनाम जैसे कुछ देश कोविड –19 से लड़ने में एक सफल उदाहरण हैं, जहां कोविड 19 के कारण एक भी मौत नहीं हुई। न्यूजीलैंड ने 28 फरवरी, 2020 को अपना पहला कोरोना वायरस मामला दर्ज किया और दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक को लागू किया। जिसके परिणामस्वरूप 8 जून, 2020 तक देश में कोई भी

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 2, Issue: 01 | January - June 2022

सक्रिय मामला दर्ज नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान भी घातक वायरस से निपटने में सफल रहे। यहां ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि इन देशों में सामाजिक दूरी के मानदंडों को अधिकतम स्तर तक लागू करने और लागू करने के लिए जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। लेकिन हमारे देश की एक बड़ी कमी यह थी कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया और वायरस की जांच में देरी हुई। कोविड–19 को संभालने में सफल राज्यों में से कुछ केरल और सिक्किम हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है इन राज्यों में जनसंख्या का घनत्व कम है। इसलिए जनसंख्या घनत्व और स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा वायरस से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में प्रमुख राज्य और शहर घनी आबादी वाले वायरस से प्रभावित हैं, जिससे अधिकारियों के लिए सामाजिक दूरी के मानदंडों और विनियमों को लागू करना और जांचना कठिन हो रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव

वैश्वीकरण ने वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर फैलने के माध्यम से समुदाय पर अपना नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित किया है। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान में उत्पन्न हुई कोविड –19 को फैलाने का एक प्रमुख माध्यम विभिन्न व्यापार, व्यवसाय, कार्य संबंधी उद्देश्यों (सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैश्वीकरण से संबंधित) के लिए यात्रियों द्वारा विदेश यात्रा करना था। यदि अधिकांश देश प्राचीन सांप्रदायिक व्यवस्था का पालन कर रहे होते तो वायरस का प्रसार इतना व्यापक नहीं होता। वर्तमान में दुनिया अत्यधिक वैश्वीकरण के चरण में थी जहां व्यवसाय, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सभी बहुत बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण के दौर से गुजर रहे थे, जिससे अंततः कई देशों के विकास को लाभ हो रहा था। भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है, के कारण भारत को एक विकासशील देश होने की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के पक्षधर हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण की परिभाषा (अस्थायी रूप से) को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, जिसे 'स्थानीयकृत वैश्वीकरण' होना चाहिए, जिससे अतीत में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के माध्यम से प्राप्त कौशल और ज्ञान को स्थानीय उद्योगों और परिचालन मानकों के विकास और विकास के लिए लागू किया जाएगा। सभी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर। स्थानीयकृत वैश्वीकरण का यह विचार एक आत्मनिर्भर घटना के विचार से जुड़ता है।

वर्ष 2020 की शुरुआत में, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि वित्तीय क्षेत्र के स्थायी मुद्दों के परिणामस्वरूप 2019–2020 में भारत की विकास दर घटकर 5 प्रतिशत होने की उम्मीद है और अर्थव्यवस्था की यह गिरावट भी खराब स्थिति का परिणाम थी। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों का प्रदर्शन। यह अनुमान भारत में कोविड –19 की शुरुआत से बहुत पहले ही प्रतिष्ठित विश्व बैंक द्वारा किया गया था। विनिर्माण उद्योगों के लिए सितंबर तिमाही में छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि ने इस क्षेत्र द्वारा जीविका के लिए संघर्ष को प्रदर्शित किया। इसके अलावा, वैश्विक एजेंसी ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) ने 2 मार्च, 2020 को अपने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान वर्ष 2020 के लिए 6.2 प्रतिशत के पहले अनुमान से घटाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया, जो कि कोविड –19 के प्रभाव के कारण होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर. इसलिए, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कोविड –19 की शुरुआत से पहले अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से योगदान देने वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट के दौर से गुजर रही थी, आगे वायरस के प्रकोप और देशव्यापी लॉकडाउन कार्यान्वयन के साथ आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है।

अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव के कारण मुख्य रूप से मांग को झटका लगा था (क्योंकि उपभोक्ता मांग में काफी गिरावट आई थी) और सरकार द्वारा लगाए गए अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान देखा गया था।

सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च की एक रिपोर्ट, दिनांक 24 जून, 2020 'कोविड–19 की शुरुआत से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था 2018 और 2019 के वैश्विक पुनरुत्थान में भाग नहीं लेते हुए, 4.5 प्रतिशत जीडीपी विकास दर तक धीमी हो गई थी।'

24 जून, 2020 को भारत के रेटिंग और रिसर्च सेंटर के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 5.3 प्रतिशत कम हो सकती है क्योंकि कोविड –19 प्रकोप के बाद के प्रभावों को वापस आने में लंबा समय लगेगा। अर्थव्यवस्था की विकास गति.

एक पैरा वाक्यांश के अनुसार 'जब अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे प्रमुख देश छींकते हैं, तो बाकी

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 2, Issue: 01 | January - June 2022

दुनिया को सर्दी लग जाती है'

उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से महामारी जैसी घटना के विकासशील और कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर इशारा करता है। यदि महामारी को चीन तक ही सीमित किया जा सकता था, तभी 'वी' आकार की रिकवरी की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन इसका असर दुनिया के 188 देशों पर पड़ा है. कई प्रमुख विश्लेषकों के अनुसार, सभी क्षेत्रों पर पड़े व्यापक प्रभाव के कारण भारत में कोविड–19 से उबरने में 'यू' या 'डब्ल्यू' आकार का वक्र होने की उम्मीद है। इसलिए भारत में महामारी का असर गहरा होगा.

निम्नलिखित ग्राफ 2019–2020 में कुल मांग की स्थिति में गिरावट को दर्शाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल, 2020 तक का यह प्रकाशन ग्राफ में दिखाया गया है

(ए) 2019–2020 की चौथी तिमाही तक दो साल की अलग–अलग तिमाहियों में जीडीपी की गिरावट की प्रवृत्ति जबकि ग्राफ में (बी) एसएआरआर (मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक वृद्धि) और जीडीपी वृद्धि वक्र प्रदर्शित किया गया है।

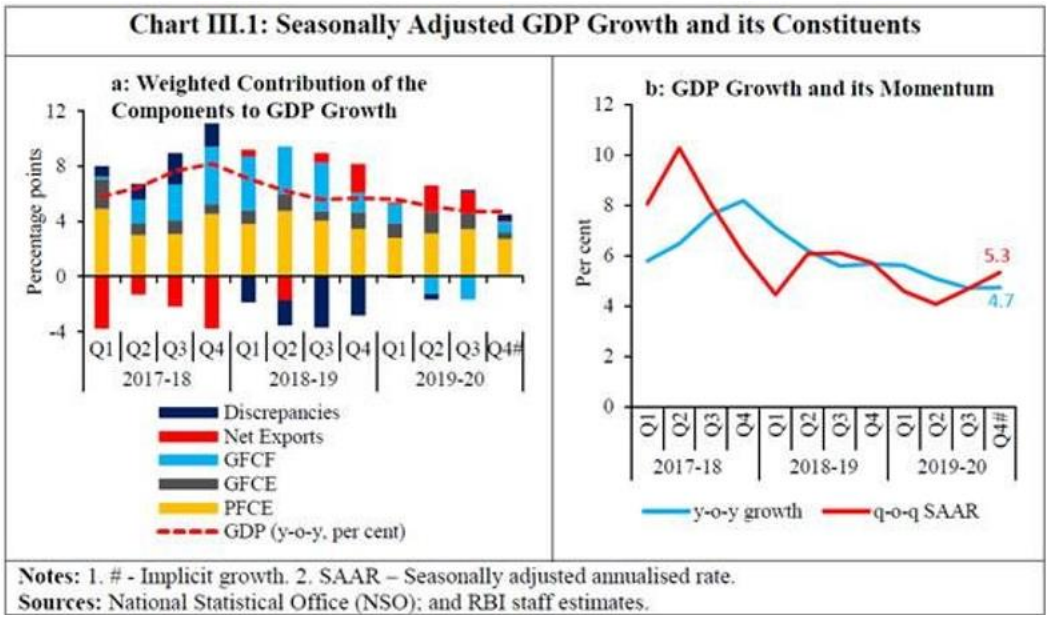

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर कोविड–19 का प्रभावः

कृषि क्षेत्रः

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण केवल आवश्यक सेवाओं को चालू रखने की अनुमति थी और उपभोक्ता मांगें भी केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीद तक ही सीमित थीं। कृषि क्षेत्र आवश्यक मानदंड के अंतर्गत आया। लेकिन एक आवश्यक श्रेणी होने के बावजूद, इस क्षेत्र में कई समस्याएं भी देखी गईं, किसानों को फसल बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन के कारण परिवहन सुविधाएं प्रभावित हुईं। कृषि उपज, प्रकृति में सबसे अधिक खराब होने वाली होने के कारण, देश भर में लॉकडाउन के कारण भोजन की गुणवत्ता में कमी आई और उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। पशुधन और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्र महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए। हालाँकि, 30 मई, 2020 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सकारात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति है। इस सकारात्मक विकास प्रवृत्ति का अंततः अर्थव्यवस्था के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नीचे दिया गया ग्राफ पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ने सहित संबद्ध गतिविधियों को दर्शाता है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) का लगभग 40 प्रतिशत है और 2012 से 2019 के दौरान समग्र कृषि जीवीए वृद्धि में चार–पांचवें योगदान देता है।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 2, Issue: 01 | January - June 2022

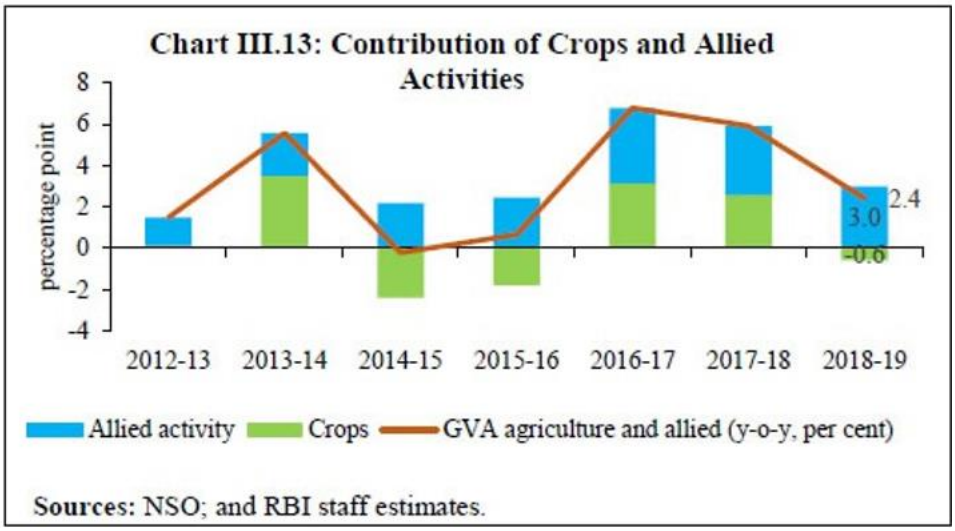

औद्योगिक क्षेत्रः

सितंबर, 2019 से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र भारी मांग और विकास में गिरावट का सामना कर रहा है। सितंबर, 2019 में भारतीय औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) में 4.3 प्रतिशत की गिरावट आई, यह सात वर्षों में सबसे कमजोर प्रदर्शन है। महामारी की शुरुआत ने स्थिति को और खराब कर दिया है। कई छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों की कमजोर स्थिति ने कमजोर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग के कारण उनके लिए जीवित रहना मुश्किल बना दिया है।

नीचे दिए गए चित्रमय प्रतिनिधित्व से पता चलता है कि बुनियादी कीमतों पर जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) वृद्धि में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान पिछले वर्ष के 1.7 प्रतिशत से घटकर 2019–2020 में 1.3 प्रतिशत हो गया है।

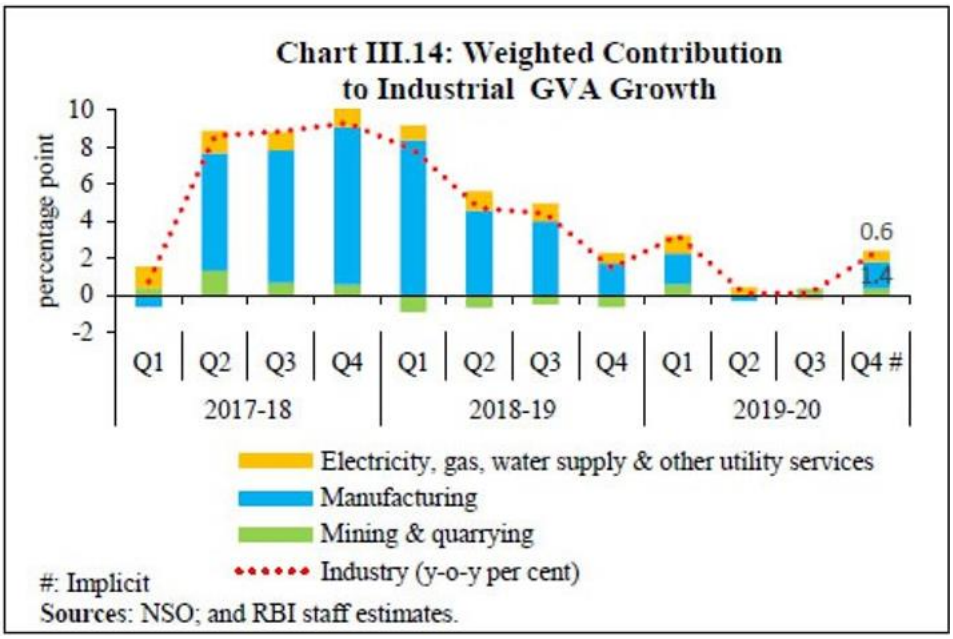

सेवा क्षेत्रः

सेवा क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जो अधिकतम कुशल श्रमिकों को रोजगार देता है और देश के जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

महामारी की शुरुआत में, व्यवसाय और सहकारी संस्थाएं शुरू में लॉकडाउन के समय बंद हो गईं और बाद में 'घर से काम' की घटना नई सामान्य हो गई। लेकिन, चूंकि समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, बहुत

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 2, Issue: 01 | January - June 2022

सारे कॉर्पोरेट कर्मचारियों को छंटनी की स्थिति का सामना करना पड़ा, वेतन में कटौती की गई क्योंकि कई कॉर्पोरेट कार्यालय घाटे वाले परिदृश्य में थे। सेवा क्षेत्र की वृद्धि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कारकों पर निर्भर है।

भारत के ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार, भारतीय सेवा क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) मई 2020 में 14.6 पर था, जो कि सीओवीआईडी –19 बंद के कारण गिरावट का संकेत देता है।

भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर महामारी का प्रभाव

भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने और विकसित होने की काफी संभावनाएं हैं। इसके कई फायदे हैं जैसे प्रचुर मात्रा में जनशक्ति (अकुशल और कुशल श्रमिक), प्राकृतिक संसाधन और प्रचुरता तथा विशाल उपभोक्ता क्रय आधार। ये सभी किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि के लिए बुनियादी तत्व हैं। हालाँकि, इन सभी पहलुओं में अग्रणी होने के बावजूद, भारतीय औद्योगिक विकास और क्षमता विकसित नहीं हो पाई है। इस दुखद स्थिति के कारणों को संक्षेप में तकनीकी पिछड़ेपन की व्यापकता, मानव शक्ति संसाधनों को महत्वपूर्ण रूप से अवशोषित करने में अक्षमता, इनपुट के लिए बाहरी बाजार की निर्भरता आदि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि चीन जैसी अन्य अग्रणी एशियाई अर्थव्यवस्था के साथ तुलना की जाती है, हमारा पड़ोसी देश अपनी लागत प्रभावी इनपुट और अच्छी गुणवत्ता वाले आउटपुट उत्पादन के कारण विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक अग्रणी विनिर्माण केंद्र रहा है। महामारी के बाद, चीन को वायरस के अंतरराष्ट्रीय प्रकोप के प्रति लापरवाही बरतने के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय आक्रोश का सामना करना पड़ा है। इस नकारात्मक प्रचार के परिणामस्वरूप, कई प्रमुख देशों ने चीनी उद्योगपति के साथ व्यापार बंद करने का फैसला किया है। चीनी व्यापारियों का यह विरोध भारतीय उद्योगपतियों के लिए एक अवसर बन सकता है क्योंकि दुनिया विकल्प तलाश रही है। समग्र औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं को निम्नानुसार उजागर किया जा सकता है:

आपूर्ति में व्यवधान

प्रारंभ में जब देश में महामारी नहीं फैली थी, तब औद्योगिक इकाइयों को परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि अधिकांश औद्योगिक इकाइयों की मशीनरी और विनिर्माण इनपुट चीन से आयात किए जाते हैं। इसके अलावा, जब महामारी देश में पहुंची और लगाए गए लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था बंद हो गई, तो सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं बंद कर दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों को सीधे आपूर्ति व्यवधान का सामना करना पड़ा, जिससे अंततः उत्पादन गतिविधियां बाधित हुईं। आवश्यक आयातित औद्योगिक इनपुट हासिल करना कठिन या महंगा हो रहा है।

मांग में व्यवधान

कुल मांग में गिरावट के कारण मांग में व्यवधान। निवेश करने में हिचकिचाहट है, अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की व्यापकता के कारण उपभोक्ता पैसा रोके हुए हैं। इसके अलावा, व्यापक बेरोजगारी के कारण, बहुसंख्यक आबादी के हाथों में नकदी प्रवाह में काफी कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप मांग में गिरावट आई है।

कार्यबल की कमी

अधिकांश उद्योगपतियों के सामने सबसे आम समस्याओं में से एक यह थी कि औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारण असंगठित कार्यबल के पास अपने मूल स्थान की ओर पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जिसके परिणामस्वरूप, अब जब औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति दी गई है, तो उद्योगपतियों को कार्यबल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो श्रमिक पलायन कर गए हैं वे भी शहरी क्षेत्रों में वापस आने से झिझक रहे हैं जहां वायरस का प्रसार बढ़ रहा है और बाजार और परिवहन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। इसने अंततः कई औद्योगिक इकाइयों की उत्पादक क्षमता के स्तर को प्रभावित किया है। 'वर्क फ्रॉम होम' की नई सामान्य घटना को समाज के इस क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि औद्योगिक संचालन के लिए दूरस्थ कार्य संभव नहीं है। विशेष रूप से मूर्त वस्तुओं को संभालने के लिए साइट पर मानव उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

लॉजिस्टिक्स को लेकर अनिश्चितता

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 2, Issue: 01 | January - June 2022

औद्योगिक इकाइयों के संचालन में लॉजिस्टिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवश्यक इनपुट का समय पर आयात और आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों को तैयार उत्पादों का निर्यात संचालन की श्रृंखला को चालू रखता है। लेकिन, देशव्यापी तालाबंदी के कारण, कई उद्योगपतियों को अटके, विलंबित और रद्द किए गए लॉजिस्टिक्स के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा। लॉजिस्टिक्स के इस व्यवधान ने उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रभावित किया और अंततः उद्योगपतियों की विश्वसनीयता पर व्यापक प्रभाव डाला क्योंकि वे इनपुट की कमी के कारण ऑर्डर आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं थे और शटडाउन के कारण उत्पादित माल भेजने में सक्षम नहीं थे। फंसे हुए माल की उपज का मूल्यह्रास भी एक बड़ी चिंता थी। इस अनिश्चितता का अंतिम परिणाम पैसे के लेन–देन में देरी के रूप में सामने आया है, जो उत्पादन की लागत में कटौती करने के लिए उद्योगपतियों के लिए श्रमिकों की छंटनी का कारण बन जाता है।
औद्योगिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) में लगभग 27 प्रतिशत योगदान देता है। सरकार ने देश की कुल जीडीपी में भारतीय उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। केंद्रीय अधिकारियों द्वारा उद्योगों को एफडीआई के माध्यम से निवेश प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने, उनके परिचालन पैटर्न को उन्नत करने, 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण पर जोर देने और संगठित करने और कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया गया है।
हालाँकि, देश में लॉकडाउन लागू करने से लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है और जून 2020 तिमाही में जीडीपी वृद्धि में भी महत्वपूर्ण गिरावट की उम्मीद है। औद्योगिक क्षेत्र में 6.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।
औद्योगिक क्षेत्र पर कोविड–19 के प्रभावों की तीव्रता की गहन समझ प्राप्त करने के लिए, उद्योग विशिष्ट सर्वेक्षण और केस अध्ययन अत्यधिक वांछनीय हैं। इस दिशा में भारतीय चमड़ा उद्योग का एक संक्षिप्त अध्ययन करके एक प्रयास किया गया है।

केस स्टडीः भारतीय चमड़ा उद्योग

भारतीय चमड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है। यह उद्योग देश के शीर्ष 10 विदेशी मुद्रा अर्जक में से एक है। भारत को तैयार चमड़े के उत्पादन में 13 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी का श्रेय दिया जाता है, जो सालाना 3 बिलियन वर्ग फुट चमड़े का उत्पादन करता है।
भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार, भारत दुनिया में चमड़े के उत्पादों और जूते का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह क्षेत्र 2.5 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और आने वाले 5 वर्षों में 2 मिलियन नौकरियां पैदा करने की क्षमता रखता है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है। यह अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र की राष्ट्र के विकास में योगदान करने की क्षमता को स्पष्ट करता है। लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र का योगदान नाममात्र का है। यह क्षेत्र भारत की जीडीपी में 1प्रतिशत से भी कम योगदान देता है। इसके अलावा, इंटरनेशनल लेदर मेकर रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के बादय वित्त वर्ष 2019–2020 में भारत के चमड़े के निर्यात में 10.89प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। इसलिए, पहले से ही योगदान का हिस्सा न्यूनतम था और अब महामारी के कारण, यह हिस्सा और भी बड़े प्रतिशत तक गिरने की उम्मीद है।
हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पशुधन की उपलब्धता के कारण भारतीय चमड़ा उद्योग के बढ़ने और अधिक सक्षमता हासिल करने की अपार संभावनाएं हैं। भारत दुनिया की 20 प्रतिशत गाय–भैंसों की आबादी और दुनिया की 11 प्रतिशत बकरी और भेड़ का घर है। ये चमड़े के उत्पाद और जूते उत्पाद बनाने के लिए बुनियादी कच्चा माल हैं। अब संभावित पहलू पर विचार करने के बाद, निर्भरता पहलू (जो विकास को बाधित करता है) पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। चीन इनपुट कच्चे माल और निर्माण के लिए आवश्यक घटकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। चीन से लेस, जूते की लाइनिंग, बकल, आभूषण, इनसोल, आउटसोल, सेलूलोज बोर्ड, शैंक बोर्ड, फोम और पैकिंग सामग्री जैसे इनपुट कारखानों को बंद करने से भारतीय चमड़ा उद्योग के लिए एक बड़ी उत्पादकता बाधा पैदा हुई है। हालाँकि, नए एमएसएमई की स्थापनाओं को बढ़ावा देकर इन सभी इनपुट सामग्रियों के विनिर्माण को बढ़ावा देकर इस स्थिति को अवसर में बदला जा सकता है। सरकार को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। यह पहल न केवल भारतीय चमड़ा उद्योग के अस्तित्व में मदद करेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी और अंततः आय में वृद्धि होगी।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 2, Issue: 01 | January - June 2022

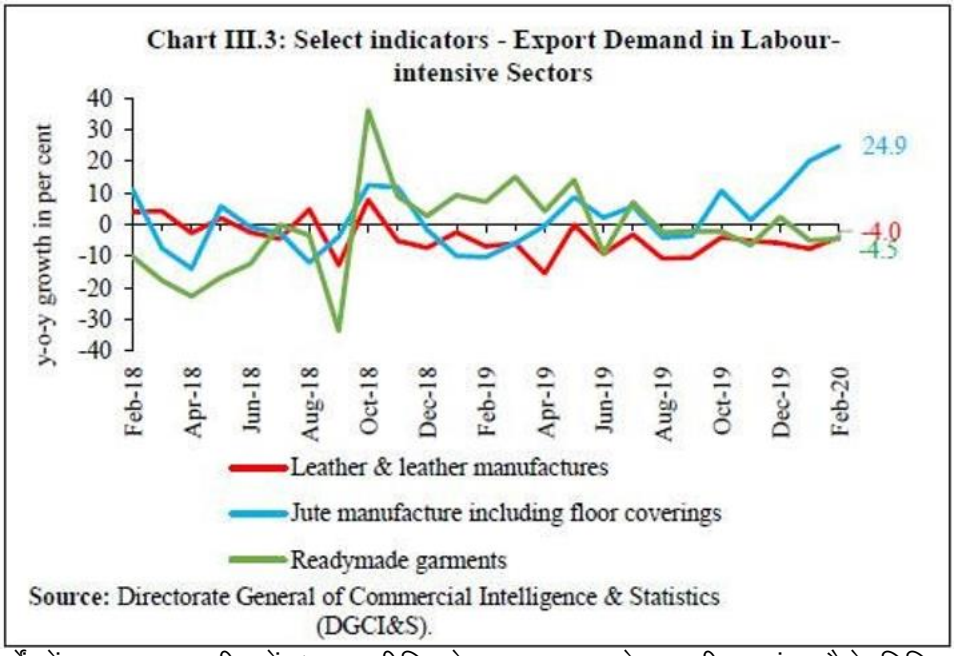

पिछले दो वर्षों में कम खाद्य कीमतों/मुद्रास्फीति के कारण कमजोर ग्रामीण मांग जैसे विभिन्न कारकों के कारण 2019–2020 में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में मंदी को दर्शाने के लिए इस संदर्भ में एक चित्रमय प्रतिनिधित्व नीचे दर्शाया गया है, ग्रामीण मजदूरी में मंदी और श्रम–प्रधान निर्यात में गिरावट का असर ग्रामीण उपभोग पर पड़ा, और घटती आय के कारण शहरी खपत में मंदी ने चमड़ा और चमड़ा निर्माताओं, जूट निर्माताओं और रेडीमेड परिधान निर्माताओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया क्योंकि वे अत्यधिक श्रम गहन हैं और उपभोक्ता मांग पर निर्भर हैं (लाल वक्र द्वारा दर्शाया गया है)।

इसलिए, उपर्युक्त केस स्टडी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर महामारी के प्रभावों को समझाने का एक प्रयास है। यह केस अध्ययन स्पष्ट रूप से संभावनाओं की व्याख्या करता है, भारतीय चमड़ा उद्योग को जनशक्ति की उपलब्धता, कच्चे माल की प्रचुरता, उदारीकरण के माध्यम से संघीय समर्थन और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के मामले में विरासत में मिला है, लेकिन फिर भी औद्योगिक क्षेत्र के इस वर्ग का प्रदर्शन असंतोषजनक है। मुख्य रूप से विनिर्माण में इनपुट के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भरता के कारण, दूसरे संसाधनों के इष्टतम उपयोग की कमी के कारण, तीसरा विनिर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञता और विशेषज्ञता के लिए इन उद्योगपतियों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों की कमी के कारण या तलाश करना। मांग में रुझान और बढ़ने और विस्तार के आगामी अवसर। ज्यादातर स्थापित और बड़े उद्योगपति विनिर्माण के पारंपरिक तरीकों का पालन करते हैं।

चमड़ा उद्योग की तरह, अन्य उद्योग भी समान स्थिति का सामना कर रहे हैं और कमोबेश समान क्षमताएं और कमियां हैं।

निष्कर्ष

कोविड–19 महामारी ने भारतीय आर्थिक संरचना की कमजोरियों और कमियों को उजागर कर दिया है। इसने विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को रेखांकित किया है और प्रचुर मानव और प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी ढंग से उपयोग के महत्व पर जोर दिया है। भारत में खुद को आगे बढ़ाकर और लागत प्रभावी, उच्च गुणवत्ता वाले सामान के उत्पादन में अपनी क्षमता साबित करके वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र को महामारी के प्रभाव से उबरना होगा, कुशलतापूर्वक वापस आना होगा और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

संदर्भ

- एस. महेंद्र देव और राजेश्वरी सेनगुप्ता (अप्रैल,2020), 'कोविड–19: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव', इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान।
- आर. जयरामन (मई, 2020) 'कोविड 19 लॉकडाउन और भारतीय विनिर्माण उद्योग– प्रभाव और पुनर्प्राप्ति' मैन्युफैक्चरिंग टुडे ई–पत्रिका।
- किशोर रोशन और झा अभिषेक (जून,2020)' विभिन्न क्षेत्रों पर कोविड–19 महामारी का आर्थिक प्रभाव' हिंदुस्तान टाइम्स ई–पेपर।
- पीटीआई (जून, 2020) 'भारत की आर्थिक सुधार 'वी' आकार की नहीं बल्कि यू–आकार की होने की संभावना है' द इकोनॉमिक टाइम्स।
- रॉयचौधरी अरूप (जून,2020) 'कोविड–19 विकार के कारण भारत की जीडीपी 5.3 प्रतिशत घट सकती है' द वायर।
- मौद्रिक नीति रिपोर्ट (अप्रैल,2020) भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशन।
- भारतीय सेवा उद्योग रिपोर्ट (जून,2020) आईबीईएफ (इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन)
- अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा निर्माता (जुलाई,2020) 'भारत का चमड़ा निर्यात।
- पीटीआई (मई, 2020) का लेख 'कोविड–19 प्रभावः भारत का निर्यात अप्रैल में रिकॉर्ड निचले स्तर 60.28 प्रतिशत पर आ गया' द न्यू इंडियन एक्सप्रेस।
- ईटी ब्यूरो (मार्च,2020), ''चीन का नुकसान भारत के लिए अवसर हो सकता है'' द इकोनॉमिक टाइम्स।